भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2955
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अंतर्गत एग्री स्टैक

2955. श्री हरीश चंद्र मीना::

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के अंतर्गत कृषि स्टैक के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार, विशेष रूप से राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर जिले में विस्तृत योजना, वर्तमान स्थिति और समय-सीमा क्या है;

(ख) कृषि स्टैक के विकास और प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कंपनियों के नाम, अवधि और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां समेत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि स्टैक पहल के लिए अन्य कंपनियों के साथ अतिरिक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के चयन के लिए मानदंडों का ब्यौरा क्या है और उनकी भागीदारी का दायरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कृषि स्टैक परियोजना शुरू करने से पहले किसान समूहों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया था; और

(च) यदि हां, तो प्राप्त फीडबैक/प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): सरकार ने एग्रीस्टैक परियोजना शुरू करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डर मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श किया है। एग्रीस्टैक में कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात् किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गांव के नक्शे और बोई गई फसल रजिस्ट्री, जो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और रखी जाती हैं। 'किसान आईडी' में किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी डेटा शामिल है, जिससे किसान ऋण, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों तक पहुँचने के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण कर सकते हैं। 17.03.2025 तक, कुल 4,35,48,601 किसान आईडी बनाए गए हैं और खरीफ 2024 में 436 जिलों में एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) किया गया है। वर्तमान में, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 17.03.2025 तक राजस्थान राज्य में 48,47,589 किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में क्रमशः 67,418 और 1,23,308 किसानों की आईडी बनाई गई हैं। इसके अलावा, 2024/25 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण क्रमशः टोंक और सवाई माधोपुर में 3,04,864 भूखंडों और 3,25,974 भूखंडों में किया गया है।

*****